

UP, Maharashtra, Gujarat account for bulk of real estate investment: Study

'90% of investments in top 10 states'

PRESS TRUST OF INDIA

Lucknow, May 9

Uttar Pradesh, Maharashtra and Gujarat account for over half of the total real estate and construction sector investments in the country as of December 2016, industry body Assocham said in a recent study.

"There are about 3,489 projects worth ₹14.5 lakh crore in the construction and real estate sector that are currently live across the country," the study titled 'Construction and real estate investment: State-level analysis' said.

Maharashtra tops

Maharashtra accounts for the lion's share of about 25 per cent in total investments followed by UP and Gujarat (13 per cent each), Karnataka (10 per cent) and Haryana (9 per cent).

"The Centre and state governments must introduce a single-window clearance system at the earliest to avoid time and cost overruns that are impacting the growth and development of real estate sector in India," Assocham national secretary general DS



There are about 3,489 projects worth ₹14.5 lakh crore in the construction and real estate sector that are currently live across the country

Rawat said here, while releasing the findings of the study.

"As for the sector, the companies in the real estate space must keep looking for long-term financial resources to become independent," he said.

Growth trends

The study prepared by Assocham Economic Research Bureau highlighted that almost 90 per cent of construction and real estate investments are concentrated in top 10 states.

So far as the investment growth trend is concerned, the sector touched highest rate of

13.5 per cent in 2010 but recorded sharp drop till 2013 whereby it recorded negative growth of about eight per cent but picked up in 2014 to reach about three per cent and again fell in 2015.

However, the real estate and construction investments recorded a positive growth rate of 2.5 per cent in 2016 and the sector clocked compounded annual growth rate (CAGR) of minus 0.7 per cent between 2011-16.

Among states, Odisha has recorded highest CAGR of about 37 per cent in realty investments during 2011-16 followed by UP (9 per cent), Maharashtra (3 per

cent), Kerala (1.6 per cent) and Andhra Pradesh (1.4 per cent) while rest all top states clocked negative growth in this regard.

About 70 per cent of construction and real estate investment projects remained non-starters in India since 2013.

Significant growth has also been recorded in projects that remained under different stages of implementation, that is, from 63 per cent in 2009 to about 77 per cent in 2015, which moderated to 72 per cent in 2016, it said.

Realty investments

Among states, over 95 per cent of realty investment projects are under implementation in West Bengal followed by UP (90 per cent) and Punjab (88 per cent).

The study noted that real estate projects in Punjab are facing maximum delays to the tune of 48 months followed by Telangana (45 months), and West Bengal, Odisha and Haryana (44 months).

On a positive note, while new investment activities in real estate and construction sector have recorded negative growth between 2011 and 2015, it recorded a significant spike in 2016 (32 per cent), it said.



Gujarat, Maha, UP account for over half of realty investment

90% of construction & realty investments are concentrated in top 10 states

DNA Correspondent @dnaahmedabad

Ahmedabad: Industry body Assocham of Tuesday said Gujarat, Uttar Pradesh and Maharashtra account for over half of the total real estate and construction sector investments in the country as of December 2016.

According to Assocham study titled 'Construction and real estate investment: State-level analysis', there are about 3,489 projects worth Rs14.5 lakh crore in the construction and real estate sector that are currently going across the country.

The study prepared by Assocham Economic Research Bureau highlighted that almost 90 per cent of construction and real estate investments are concentrated in top 10 states.

Top players

Maharashtra accounts for the lion's share of about 25 per cent in total investments followed by UP and Gujarat (13 per cent each), Karnataka (10 per cent) and Haryana (9 per cent).

"The Centre and state governments must introduce a single-window clearance system at the earliest to avoid time and cost overruns that are impacting the growth and development of real estate sector in India," said national secretary general of Assocham D S Rawat while releasing the study.

However, the real estate and construction investments recorded a positive growth rate of 2.5 per cent in 2016 as such the sector clocked compounded annual growth rate (CAGR) of minus 0.7 per cent between 2011-16.

महाराष्ट्र में आया सबसे ज्यादा निवेश

► इस मामले में यूपी और गुजरात संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर : एसोचैम

■ लखनऊ।

देश के रीयल एस्टेट तथा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने औरों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। उद्योग मंडल 'एसोचैम' की रिपोर्ट के मुताबिक रीयल्टी और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इन राज्यों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से ऊपर है।

एसोचैम द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार दिसम्बर 2016 तक देश में

14.5 लाख करोड़ रुपए की 3489 रीयल एस्टेट परियोजनाएं चल रही थीं। इनमें हुए कुल निवेश में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात (13-13 प्रतिशत), कर्नाटक (10 फीसद) तथा हरियाणा (नौ प्रतिशत)



का स्थान है। एसोचैम के राष्ट्रीय महासचिव डी. एस. रावत ने यहां बताया कि जहां तक रीयल एस्टेट क्षेत्र का सवाल है तो कंपनियों को भविष्य में स्वतंत्रतापूर्वक काम करने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों की तलाश पर ध्यान देना होगा।

रीयल्टी तथा विनिर्माण क्षेत्र में और तेजी लाने के लिए उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को जल्द से जल्द एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण कारोबार पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को टाला जा सके। एसोचैम के आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार रीयल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र में हुआ करीब 90 प्रतिशत निवेश देश के शीर्ष 10 राज्यों में ही हुआ है। ■ भाषा

रिपोर्ट

रीयल्टी सेक्टर में हुए कुल निवेश का 50 फीसद सिर्फ महाराष्ट्र में ही हुआ यूपी और गुजरात में कुल 13-13 फीसद हुआ निवेश

कर्नाटक में 10 और हरियाणा में नौ फीसद निवेश

निर्माण क्षेत्र के निवेश में 2.5 फीसद वृद्धि

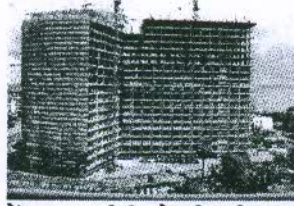
एसोचैम की रिपोर्ट...

महाराष्ट्र व यूपी रियल एस्टेट में आगे

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

लखनऊ. देश के रियल एस्टेट तथा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने अन्य राज्यों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। उद्योग मण्डल एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक रियल्टी और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इन राज्यों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से ऊपर है। एसोचैम की ओर से कराए गए अध्ययन के अनुसार दिसम्बर 2016 तक देश में चल रही 14.5 लाख करोड़ रुपए की 3489 रियल एस्टेट परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें हुए कुल निवेश



में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात 13-13 प्रतिशत, कर्नाटक 10 फीसदी तथा हरियाणा नौ प्रतिशत का स्थान है। एसोचैम ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र का सवाल है तो कम्पनियों को भविष्य में स्वतंत्रतापूर्वक काम करने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों की तलाश पर ध्यान देना होगा।

सिंगल विंडो सिस्टम जरूरी

रियल्टी तथा विनिर्माण क्षेत्र में और तेजी लाने के लिए एसोचैम ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को जल्द से जल्द एकल खिड़की प्रणाली की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि परियोजनाओं के फिनांचियल में विलम्ब के कारण कारोबार पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को टाला जा सके। एसोचैम के आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

महाराष्ट्र, उप्र और गुजरात हैं रियल एस्टेट में आगे

लखनऊ, भाषा। देश के रियल एस्टेट तथा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने औरों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। उद्योग मण्डल 'एसोचेम' की रिपोर्ट के मुताबिक रियलिटी और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इन राज्यों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से उपर है।

एसोचेम द्वारा कराये गये 'विनिर्माण एवं रियल एस्टेट निवेश: राज्य स्तरीय विश्लेषण' विषयक अध्ययन के अनुसार दिसम्बर 2016 तक देश में चल रही 14 . 5 लाख करोड़ रुपये की 3489 रियल एस्टेट परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें हुए कुल निवेश में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात (13-13 प्रतिशत), कर्नाटक (10 फीसद) तथा हरियाणा (नौ प्रतिशत) का स्थान है।

एसोचेम के राष्ट्रीय महासचिव डी. एस. रावत ने यहां बताया कि जहां तक रियल एस्टेट क्षेत्र का सवाल है तो कम्पनियों को भविष्य में स्वतंत्रतापूर्वक काम करने के लिये दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों की तलाश पर ध्यान देना होगा।

